

ग्लोबल टॉचर इंडेक्स 2025: इंडिया फैक्टशीट

ग्लोबल टॉचर इंडेक्स स्कोर:

उच्च जोखिम

ग्लोबल टॉचर इंडेक्स 2025 दुनिया भर के 26 देशों में यातना और दुर्व्यवहार के जोखिम का आकलन करने के लिए डिज़ाइन किया गया पहला विश्लेषण है। भारत के लिए 2025 की इस फैक्टशीट में देश के समग्र प्रदर्शन का विश्लेषण, विषयगत स्तंभों द्वारा टूटना और यातना के खिलाफ लड़ाई और मानवाधिकारों को बढ़ावा देने में सार्थक बदलाव लाने के लिए प्रमुख सिफारिशें शामिल हैं।

भारत में सहयोगी संगठन:

People's Watch

एक नजर में

यातना, जो विशेष रूप से भारत में यातना, विशेष रूप से कानून प्रवर्तन अभियानों और पूछताछ के दौरान पुलिस तथा सुरक्षा बलों द्वारा, व्यापक और व्यवस्थित रूप से की जाती है। 2025 के लिए, ग्लोबल टॉचर इंडेक्स ने 2023 और 2024 में संकलित आँकड़ों के आधार पर भारत को यातना और दुर्व्यवहार के उच्च जोखिम वाले देशों में वर्गीकृत किया है।

गंभीर पिटाई, जबरन स्वीकारोक्ति तथा हिरासत में मौत जैसी घटनाएँ प्रायः घटित होती हैं, जिनका प्रभाव विशेष रूप से दलित, आदिवासी, मुस्लिम, एलजीबीटीक्यूआईए+ समुदाय तथा प्रवासी मजदूरों जैसे हाशिए पर स्थित समूहों पर अधिक देखा जाता है। पश्चिम बंगाल के निवासी, विशेष रूप से भारत-बांग्लादेश सीमा के पास, [राज्य बलों द्वारा नियमित हिंसा, यातना और असाधारण हत्याओं का सामना करते हैं](#)।

सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) को दी गई कानूनी दण्डमुक्ति पीड़ितों के लिए जवाबदेही और न्याय में गंभीर रूप से बाधा डालती है। सामान्य प्रथाओं में अनौपचारिक स्थानों में गैरकानूनी हिरासत और असाधारण हत्याएं शामिल हैं, जिन्हें अक्सर पुलिस कर्मियों के लिए पदोन्नति के साथ पुरस्कृत किया जाता है। मानवाधिकार रक्षकों को नियमित रूप से मनमानी गिरफ्तारी, निवारक हिरासत और यातना और दुर्व्यवहार के अधीन किया जाता है, जो संस्थागत हिंसा और दण्डमुक्ति की संस्कृति को रेखांकित करता है। भारत का राजनीतिक और संस्थागत ढांचा इस संकट में महत्वपूर्ण योगदान देता है। यातना पर संवैधानिक प्रतिबंधों के बावजूद, यातना या CIDTP को अपराध बनाने वाला कोई विशिष्ट राष्ट्रीय कानून नहीं है, और यातना के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन (UNCAT) और इसके वैकल्पिक प्रोटोकॉल सहित प्रमुख अंतरराष्ट्रीय संधियाँ अपुष्ट हैं। गैरकानूनी गतिविधियाँ (रोकथाम) अधिनियम (UAPA) में 2019 के संशोधन ने कार्यकर्ताओं को मनमाने ढंग से आतंकवादी के रूप में लेबल करने में सक्षम बनाया है, जिससे असंतोष का दमन तेज हो गया है। हालांकि औपचारिक रूप से अंतरराष्ट्रीय निरीक्षण को आमंत्रित करते हुए, भारत यातना पर संयुक्त राष्ट्र के विशेष दूत जैसे तंत्रों द्वारा यात्राओं को प्रभावी ढंग से रोकता है, जो यातना को व्यापक रूप से संबोधित करने के लिए अपर्याप्त राजनीतिक प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

2024 में, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) ने रिपोर्ट किया कि 2023 में दर्ज 2,739 मामलों में लगभग 2,400 मामले हिरासत में मौत से संबंधित थे। इसके अतिरिक्त, 2022 में न्यायिक हिरासत में 1,995 कैदियों की मौत हुई, जिसमें 159 अप्राकृतिक मौतें शामिल हैं। 2018 से यूएपीए के तहत कम से कम 61 मानवाधिकार रक्षकों को हिरासत में लिया गया है। हाई-प्रोफाइल मामलों में कार्यकर्ता प्रोफेसर जीएन साईबाबा की विस्तारित कैद और बाद में मौत शामिल है, जिन्हें गंभीर विकलांगता होने के बावजूद हिरासत में लिया गया था, और पत्रकार सिद्दीक कप्पन जाति हिंसा की जांच के लिए दो साल की कैद की सजा सुनाई गई थी।

यातना और दुर्व्यवहार के पीड़ितों के अधिकार गंभीर रूप से सीमित बने हुए हैं, क्योंकि पीड़ितों को परिभाषित करने वाला कोई व्यापक कानून अस्तित्व में नहीं है। परिणामस्वरूप, अधिकांश बचे हुए व्यक्तियों को पर्याप्त निवारण या पुनर्वास उपलब्ध नहीं हो

पाता। मौजूदा शिकायत तंत्र प्रायः अप्रभावी साबित होते हैं और कई मामलों में शिकायतकर्ताओं को प्रतिशोध का सामना करना पड़ता है। यद्यपि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) मौजूद है, लेकिन उसे अपर्याप्त स्वतंत्रता और पीड़ितों की आवश्यकताओं के प्रति कमजोर प्रतिक्रियाओं के लिए निरंतर आलोचना झेलनी पड़ती है।

सामान्य जानकारी

						
मानवाधिकार रक्षकों की दर्ज और हिरासत में ली गई घटनाएँ	यातना के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन: पुष्टि नहीं की गई	ओपीसीएटी अनुसमर्थन: पुष्टि नहीं की गई	आबादी: 1.460.736.310	स्वतंत्रता से वंचित लोग: 573,220	जेल की आबादी (राष्ट्रीय जनसंख्या के प्रति 100,000): 41	पूर्व-परीक्षण बंदियों / रिमांड कैदियों (जेल की आबादी का प्रतिशत): 75.8%
						
रक्षक: कोई डेटा नहीं	जारी अलर्ट 2024 में रक्षक: 11		लोग: 3			

विषय अवलोकन और विश्लेषण

I. राजनीतिक प्रतिबद्धता

इंडेक्स स्कोर: महत्वपूर्ण जोखिम

भारत यातना और अन्य क्रूर, अमानवीय या अपमानजनक व्यवहार या सजा (CIDTP) को प्रभावी ढंग से रोकने के लिए अपर्याप्त राजनीतिक प्रतिबद्धता प्रदर्शित करता है। संवैधानिक निषेधों के बावजूद, देश में विशेष रूप से यातना या CIDTP को आपराधिक बनाने वाले समर्पित राष्ट्रीय कानून का अभाव है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन (UNCAT) सहित प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय लिखतों को भी अनुमोदित नहीं किया है, जिनमें बार-बार की गई UPR सिफारिशें, इसके वैकल्पिक प्रोटोकॉल (OPCAT), ICCPR का दूसरा वैकल्पिक प्रोटोकॉल (मृत्युदंड समाप्त करने के उद्देश्य से), और जबरन गुमशुदगी से सभी व्यक्तियों के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन शामिल हैं।

जुलाई 2019 में संशोधित एक प्रतिगामी आतंकवाद-विरोधी कानून, गैरकानूनी गतिविधियाँ (रोकथाम) अधिनियम (UAPA) ने अधिकारियों को कार्यकर्ताओं और मानवाधिकार रक्षकों सहित व्यक्तियों को आतंकवादी घोषित करने की शक्ति देकर स्थिति को और गंभीर बना दिया है। 2018 के बाद से, कम से कम 61 एचआरडी को यूएपीए और/या आतंक/सुरक्षा कानूनों के तहत जेल में बंद किया गया है।

भारत ने हाल ही में तीन नए कानूनों को पेश करके अपने आपराधिक कानूनी ढांचे को बदल दिया: भारतीय न्याय संहिता, 2023 (BNS), जो भारतीय दंड संहिता (जैसे स्वीकारोक्ति वसूलने पर धारा 120); भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (BNSS), जो आपराधिक प्रक्रिया संहिता की जगह लेता है; और भारतीय साक्षी विधेयक, 2023 (BSB), जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम की जगह लेता है।

भारत का अंतर्राष्ट्रीय निरीक्षण तंत्रों के साथ न्यूनतम जुड़ाव है। हालांकि सरकार ने औपचारिक रूप से यातना पर संयुक्त राष्ट्र के विशेष दूत को देश का दौरा करने के लिए आमंत्रित किया, लेकिन इसने इस तरह की यात्राओं को होने से प्रभावी ढंग से रोका है। इसने पिछले पांच वर्षों में प्रतिवेदक से 50% से कम संचार का जवाब दिया है और न्यूनतम ठोस जानकारी प्रदान की है।



II. पुलिस की बर्बरता को समाप्त करना और संस्थागत हिंसा

इंडेक्स स्कोर: हाई रिस्क

पुलिस की बर्बरता और संस्थागत हिंसा भारत में प्रचलित और व्यवस्थित बनी हुई है, जो कानून प्रवर्तन अधिकारियों द्वारा यातना, दुर्व्यवहार और असाधारण हत्याओं की लगातार घटनाओं की विशेषता है। दिसंबर 2020 के परिमवीर सिंह बनाम बलजीत सिंह मामले में, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने पुलिस स्टेशनों और केंद्रीय जांच एजेंसी कार्यालयों में सीसीटीवी कैमरों की स्थापना को अनिवार्य करने के लिए दिशानिर्देश जारी किए, जिसमें कैमरा फीचर्स, प्लेसमेंट और फुटेज के भंडारण और पहुंच जैसे पहलुओं को शामिल किया गया। हालांकि, अनुपालन खराब बना हुआ है, क्योंकि 2,701 पुलिस स्टेशनों में किसी भी प्रकार के निगरानी कैमरे नहीं हैं। जहां कैमरे लगाए गए हैं, उनमें से अधिकांश न्यायालय द्वारा निर्धारित मानकों को कवरेज, तकनीकी विशेषताओं और डेटा भंडारण क्षमता के संदर्भ में पूरा करने में असफल हैं।

हिरासत में हिंसा व्यापक है, जिसके परिणामस्वरूप मौतें अक्सर बंदियों के स्थानांतरण के दौरान या पुलिस स्टेशनों और अस्पतालों में होती हैं। कानून प्रवर्तन अधिकारी नियमित रूप से गिरफ्तारी से पहले और दौरान जानकारी निकालने के लिए पिटाई, धमकी और अन्य अवैध प्रथाओं का सहारा लेते हैं। हथियारों के अनुचित उपयोग से गंभीर चोटें और मौतें हुई हैं जिनका प्रभाव विशेष रूप से दलित, आदिवासी, मुस्लिम, LGBTQIA+ व्यक्तियों, प्रवासी मजदूरों और बेघर व्यक्तियों जैसे हाशिए पर स्थित समूहों पर पड़ा है। ये समूह नियमित रूप से गंभीर शारीरिक शोषण, दखल देने वाली बॉडी चेक और भेदभावपूर्ण पुलिसिंग प्रथाओं का सामना करते हैं। हिरासत के अनौपचारिक स्थल—जिनमें परित्यक्त इमारतें, सरकारी कार्यालय और यहां तक कि होटल के कमरे शामिल हैं—पुलिस की बर्बरता के आम केंद्र बन गए हैं, जहाँ बंदियों को जबरन स्वीकारोक्ति दिलाने के लिए पिटाई, धमकी और अन्य प्रकार के दुर्व्यवहार का सामना करना पड़ता है।

नए प्रक्रियात्मक कानूनों के तहत, सार्वजनिक अधिकारियों पर मुकदमा चलाने के लिए कार्यकारी मंजूरी की आवश्यकता बनी हुई है, हालांकि एक नए प्रावधान का उद्देश्य हिरासत में हिंसा के मामलों में इस बाधा को कम करना है। इसके अनुसार, यदि मंजूरी देने वाला प्राधिकारी 120 दिनों के भीतर जवाब देने में विफल रहता है, तो अनुमोदन को स्वीकृत माना जाएगा। इसके बावजूद, कानून जांच के दौरान पुलिस हिरासत की अनुमय अवधि को भी महत्वपूर्ण रूप से बढ़ाता है, जिससे हिरासत में हिंसा की संभावना बनी रहती है।

न्यायिक हस्तक्षेप के बावजूद, जवाबदेही कम बनी हुई है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने 2024 में लगभग 2,739 हिरासत में मौतों और 2023 में लगभग 2,400 मामलों की रिपोर्ट की है। 'एनकाउंटर स्पेशलिस्ट' कहे जाने वाले पुलिस अधिकारियों को गैर-न्यायिक हत्याएं करने के लिए पदोन्नति मिलती है, जो संस्थागत मिलीभगत का प्रदर्शन करते हैं। मानवाधिकार रक्षक, विशेष रूप से भूमि और पर्यावरण के मुद्दों को संबोधित करने वाले, अक्सर निवारक हिरासत, यातना और अवैध गिरफ्तारी का सामना करते हैं।



III. यातना से मुक्ति जबकि स्वतंत्रता से वंचित

इंडेक्स स्कोर: हाई रिस्क

भारत में स्वतंत्रता से वंचित व्यक्तियों को गंभीर और व्यवस्थित मानव अधिकारों के उल्लंघन का सामना करना पड़ता है। सिर्फ 2022 में न्यायिक हिरासत में कुल 1,995 कैदियों की मौत हुई, जिसमें 159 अप्राकृतिक मौतें शामिल हैं, जो निरोध सुविधाओं में खतरनाक स्थितियों को उजागर करती हैं। 2022 के लिए राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) जेल के आंकड़ों के अनुसार, भीड़भाड़ इस स्थिति को काफी बढ़ा देती है, क्योंकि जेलें राष्ट्रीय औसत 131.4% अधिभोग दर पर संचालित हो रही हैं। यह अत्यधिक भीड़ गरीब कैदियों को असमान रूप से प्रभावित करती है, जो अपर्याप्त भोजन, कपड़े और बिस्तर जैसी बुनियादी सुविधाओं की कमी से गंभीर रूप से पीड़ित हैं, जिससे उनकी रहने की स्थितियाँ और अधिक बिगड़ जाती हैं।

भारतीय जेलों में हाशिए के समुदायों के खिलाफ भेदभाव खतरनाक रूप से प्रचलित है, जो मुख्य रूप से जाति, धर्म, आर्थिक स्थिति, विकलांगता और यौन अभिविन्यास से प्रभावित है। संस्थागत उपेक्षा को दर्शाने वाला एक उल्लेखनीय मामला प्रोफेसर बीएन साईबाबा से जुड़ा है, जिन्होंने 90 फीसदी विकलांग और वृद्धि पर रहने के बावजूद, पर्याप्त सुविधाओं के बिना 10 साल से अधिक समय तक जेल में बिताया, जिससे उनका स्वास्थ्य गंभीर रूप से बिगड़ गया। उसे 9 मई, 2014 को दिल्ली में मनमाने ढंग से गिरफ्तार किया गया था और 7 मार्च, 2017 को साजिश रचने और गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम कानून के तहत आतंकवादी संगठन की सदस्यता के आरोप में उग्रकैद की सजा सुनाई गई थी। 2018 में, तंत्रिका क्षति और पर्याप्त चिकित्सा की कमी के कारण उनका बायां हाथ लकवाग्रस्त हो गया था। यातना या दुर्व्यवहार का सामना करने वाले बंदियों के लिए शिकायत तंत्र काफी हद तक अप्रभावी हैं। स्वतंत्र चिकित्सा मूल्यांकन शायद ही कभी हस्तक्षेप के बिना होते हैं, और यातना के आरोपी कर्मचारियों को जांच के दौरान शायद ही कभी निलंबित कर दिया जाता है। दुर्व्यवहार की रिपोर्ट करने वाले कैदियों को अक्सर बढ़ी हुई तलाशी, अनुचित दंड, एकान्त कारावास, धमकी और यहां तक कि मौत जैसे प्रतिशोध का सामना करना पड़ता है।

इसके अलावा, गृह मंत्रालय और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के आँकड़े वर्ष 2022 और 2023 के बीच पश्चिम बंगाल में पुलिस हिरासत में मौतों में 300% की वृद्धि दर्शाते हैं। भारत में आपराधिक जिम्मेदारी की न्यूनतम आयु चिंताजनक रूप से कम है, जो केवल 8 वर्ष है।

जबकि नागरिक समाज के सदस्यों द्वारा गैर-आधिकारिक जेल यात्राओं की अनुमति देने वाले सैद्धांतिक प्रावधान हैं, व्यवहार में, पहुंच प्रतिबंधित है, एचआरडी को अक्सर हिरासत सुविधाओं के भीतर सार्वजनिक रूप से दस्तावेजीकरण स्थितियों के लिए प्रतिशोध का सामना करना पड़ता है।



IV. दण्डमुक्ति समाप्त करना

इंडेक्स स्कोर: हाई रिस्क

महत्वपूर्ण कानूनी और संस्थागत कमियों के कारण भारत में यातना के लिए दण्डमुक्ति व्याप्त है। देश में व्यापक घरेलू कानून का अभाव है जो स्पष्ट रूप से यातना का अपराधीकरण करता है, मामलों को आमतौर पर पुलिस या न्यायिक हिरासत में मौतों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। पीड़ित और गवाह संरक्षण कानूनों की अनुपस्थिति रिपोर्टिंग को गंभीर रूप से हतोत्साहित करती है, एक ऐसी स्थिति जिसे सुप्रीम कोर्ट के 2018 के फैसले (महेंद्र चावला और अन्य बनाम भारत संघ) द्वारा केवल आंशिक रूप से संबोधित किया गया है। फिर भी, पीड़ित शायद ही कभी लंबी न्यायिक प्रक्रियाओं के कारण कानूनी सहायता प्राप्त करते हैं, और अक्सर समाधान के बिना कई वर्षों तक विस्तारित होते हैं।

राष्ट्रीय और राज्य मानवाधिकार आयोगों सहित संस्थागत तंत्रों में सशस्त्र बलों द्वारा उल्लंघनों पर अधिकार क्षेत्र का अभाव है, जिससे जवाबदेही में और कमियां पैदा होती हैं। मार्च 2025 में आयोजित अपने 45वें सत्र के दौरान, ग्लोबल अलायंस ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट्स इंस्टीट्यूट्स (GANHRI) ने भारत के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) को 'A' से 'B' की स्थिति में डाउनग्रेड करने की सिफारिश की है, जिसमें जांच में पुलिस अधिकारियों की भागीदारी शामिल है, जो इसकी निष्पक्षता को प्रभावित कर सकती है। इसके अलावा, GANHRI ने इस बात पर प्रकाश डाला कि एनएचआरसी ने 'सिकुड़ते नागरिक स्थान और मानवाधिकार रक्षकों, पत्रकारों और कथित आलोचकों को निशाना बनाने की बढ़ती घटनाओं' पर ध्यान नहीं दिया है।

सीमित फोरेंसिक जांच क्षमता इस मुद्दे को जटिल बनाती है, क्योंकि फोरेंसिक संस्थानों को नियंत्रित करने वाला कोई राष्ट्रीय कानून नहीं है या अंतरराष्ट्रीय मानकों का पालन अनिवार्य नहीं है। यह यातना जांच में सटीक और निष्पक्ष सबूत एकत्र करने के लिए और चुनौतियां पैदा करता है।

कथित अपराधियों के खिलाफ मामलों में अक्सर दोषसिद्धि होती है, जिससे दण्ड मुक्ति को बल मिलता है। पीड़ितों, गवाहों और वकीलों को डराने-धमकाने और कलंकित करने जैसे प्रतिशोध आम हैं, और पुलिस और अभियोजक अक्सर शिकायत दर्ज करने को सक्रिय रूप से हतोत्साहित करते हैं।



बहुत। पीड़ितों के अधिकार

इंडेक्स स्कोर: हाई रिस्क

भारत में यातना और दुर्व्यवहार के पीड़ितों के लिए मौजूदा सुरक्षा उपायों के कार्यान्वयन में गंभीर विधायी खामियाँ और अपर्याप्तताएँ हैं। वर्तमान में, यातना के पीड़ितों को परिभाषित करने वाला कोई समग्र राष्ट्रीय कानून मौजूद नहीं है, हालांकि कुछ बिखरे हुए कानूनी प्रावधान विशिष्ट समूहों के लिए सीमित सुरक्षा प्रदान करते हैं। इससे पीड़ितों के लिए न्याय और प्रभावी निवारण तक पहुँच अत्यंत सीमित हो जाती है। कुछ उदाहरण हाई-प्रोफाइल घटनाएँ हैं जैसे कि चेन्नई में विग्नेश की हिरासत में मौत और तमिलनाडु के चेंगलपट्टूर में एक विशेष किशोर गृह में एक किशोर की क्रूर हत्या, कमजोर समूहों के लिए डिज़ाइन किए गए सुरक्षात्मक कानूनों के अप्रभावी अनुप्रयोग को उजागर करती है। पीड़ितों और उनके परिवारों को सार्थक निवारण प्राप्त करने के लिए लगातार संघर्ष करना पड़ता है, जो जवाबदेही तंत्र और न्यायिक प्रक्रियाओं दोनों में प्रणालीगत कमजोरियों को दर्शाता है। इसके अलावा, यातना पीड़ितों के लिए मुआवजा दुर्लभ और अपर्याप्त है; अनुमान बताते हैं कि यातना से बचे लोगों में से केवल 0-25% को कोई वित्तीय क्षतिपूर्ति प्राप्त होती है। संस्थागत उपेक्षा का व्यापक मुद्दा और व्यापक पीड़ित सहायता तंत्र की कमी अधिकांश यातना बचे लोगों को पर्याप्त मनोवैज्ञानिक सहायता, चिकित्सा देखभाल या न्याय के बिना छोड़ देती है।



VI. सभी के लिए सुरक्षा

भारत में, कई कमजोर समूहों के लिए सुरक्षा में महत्वपूर्ण कमी है। पिछले पांच वर्षों में महिलाओं और लड़कियों के खिलाफ ऑनर किलिंग में वृद्धि हुई है; हालांकि, मामलों की रिपोर्ट कम की जाती है, और कोई सटीक आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। इस सामाजिक दुर्दशा के बने रहने के बावजूद, भारत में इसे संबोधित करने के लिए विशिष्ट कानून का अभाव है, हालांकि विधि आयोग की रिपोर्ट संख्या 242 में एक मसौदा प्रस्तावित किया गया था। रिपोर्टों में महिलाओं और लड़कियों के विरुद्ध स्थानिक हिंसा का संकेत मिलता है, जो वैवाहिक और सामूहिक बलात्कार, घरेलू हिंसा, एसिड हमलों और सार्वजनिक अपमान सहित प्रथाओं द्वारा प्रकट होता है, जिसमें नग्न महिलाओं को सड़कों पर परेड किया जाता है, बलात्कार के मामलों को अक्सर गलत तरीके से संभाला जाता है, न्यायाधीश अक्सर पीडित-दोष में संलग्न होते हैं और उत्तरजीवियों पर सबूत का अनुचित रूप से भारी बोझ डालते हैं, जिससे न्याय प्राप्त करना मुश्किल हो जाता है। जबरन और बाल विवाह प्रचलित हैं, और सरकार शायद ही कभी उन्हें मिटाने के लिए प्रभावी उपाय करती है। इसके अतिरिक्त, महिला जननांग विकृति पर्याप्त राज्य हस्तक्षेप या निवारक नीतियों के बिना बनी है। भारतीय न्याय संहिता, 2023 के तहत बलात्कार की परिभाषा में वैवाहिक बलात्कार शामिल नहीं है।

बच्चों को भी खतरनाक शोषण का सामना करना पड़ता है। बंधुआ मजदूरी व्यापक रूप से बनी हुई है, जिसमें बच्चों को आमतौर पर भीख मांगने, वेश्यावृत्ति, अंग तस्करी और खतरनाक रोजगार के लिए मजबूर किया जाता है, जैसे पटाखे बनाना और अन्य खतरनाक मौसमी व्यवसायों में संलग्न होना।

2024 में प्रकाशित एक अध्ययन से पता चला है कि भारत में 9,600 वर्षों में वयस्क जेल में 6 से अधिक बच्चे 'गलत तरीके से' जेल में बंद थे।

भारत के स्वदेशी समुदाय, जिन्हें कानूनी रूप से 'अनुसूचित जनजाति' कहा जाता है या आमतौर पर आदिवासी के रूप में जाना जाता है, अक्सर हाशिए पर जाने का सामना करते हैं, सार्थक भागीदारी की कमी होती है और निष्कर्षण उद्योगों, ऊर्जा परियोजनाओं और अवैध गतिविधियों से जुड़े भूमि और संसाधनों पर संघर्ष का अनुभव करते हैं। भारत के पूर्वोत्तर राज्य मणिपुर में, समुदाय लगभग दो वर्षों से जातीय हिंसा से त्रस्त है, और राज्य सुरक्षा बलों ने 260 से अधिक लोगों को मार डाला है और **60,000** से अधिक विस्थापित हुए हैं।

राष्ट्रीय सुरक्षा के संदर्भ में, व्यक्तियों को आतंकवाद विरोधी आरोपों के तहत पूछताछ के दौरान लगातार दुर्व्यवहार, यातना और मौत का सामना करना पड़ता है। उदाहरण के लिए, व्हीलचेयर पर 90 फीसदी रहने वाले कार्यकर्ता जीएन साईबाबा को नागपुर जेल में उचित चिकित्सा देखभाल के बिना सात साल तक क्रूर उपचार का सामना करना पड़ा। पत्रकार सिद्दीक कप्पन को जाति-आधारित भेदभाव को उजागर करने के लिए आतंकवाद के आरोपों के तहत हिरासत में लिया गया था। 169 से अधिक मानवाधिकार संस्थानों की उपस्थिति के बावजूद, निरोध केंद्रों की प्रभावी निगरानी गंभीर रूप से सीमित है, जिससे असूचित उल्लंघनों की सुविधा मिलती है।



VII. सुरक्षा का अधिकार और नागरिक क्षेत्र

भारत में, भाषण, अभिव्यक्ति, एकत्र होने और संगठन बनाने की स्वतंत्रता के संवैधानिक संरक्षण के बावजूद, मानवाधिकार रक्षकों (एचआरडी) और नागरिक समाज संगठनों को अक्सर गंभीर प्रतिबंधों और धमकी का सामना करना पड़ता है। विदेशी अंशदान (विनियमन) अधिनियम, 2010 के दुरुपयोग के कारण **30,000** से अधिक गैर सरकारी संगठनों ने परिचालन क्षमता खो दी है, विशेष रूप से इसके कड़े 2020 संशोधनों के परिणामस्वरूप। राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) और केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) जैसी एजेंसियों द्वारा गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए), धन शोधन निवारण अधिनियम और विभिन्न निवारक निरोध कानूनों जैसे कानूनों के अतिरिक्त दुरुपयोग ने नागरिक स्वतंत्रता को गंभीर रूप से कम कर दिया है। 2002 के गुजरात दंगों सहित पिछले उल्लंघनों और पीड़ितों के लिए न्याय के लिए जवाबदेही की मांग करने वाले एचआरडी को कानूनी मामलों के साथ निशाना बनाया गया है और उनके काम के प्रतिशोध में जेल में डाल दिया गया है।

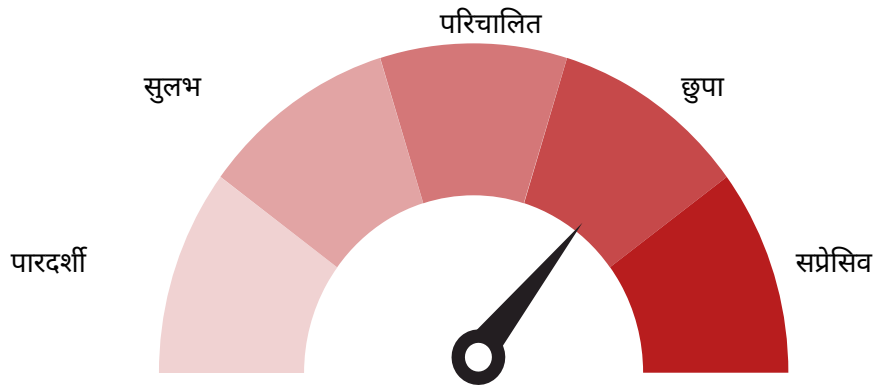
प्रमुख उदाहरणों में भीमा कोरेगांव मामला शामिल है, जहां कार्यकर्ता, वकील और शोधकर्ता पांच साल से अधिक समय से जेल में बंद हैं। इसी तरह, कश्मीरी कार्यकर्ता खुर्रम परवेज़ को तीन साल से अधिक समय तक जेल में रखा गया है, जबकि **90%** शारीरिक रूप से विकलांग प्रोफेसर जीएन साईबाबा को **8.5** साल जेल में रहने के बाद बरी कर दिया गया था, और छह महीने बाद उनकी मृत्यु हो गई थी। हाथरस में जाति आधारित हिंसा की जांच करने का प्रयास करने के लिए पत्रकार सिद्दीक कप्पन को दो साल की कैद का सामना करना पड़ा। तीस्ता सीतलवाड़ और सेवानिवृत्त आईपीएस अधिकारी श्रीकुमार जैसे कार्यकर्ताओं को सुप्रीम कोर्ट के संदर्भों के 10 सप्ताह से अधिक समय बाद न्यायिक हिरासत का सामना करना पड़ा।

सार्वजनिक सभाओं की निगरानी के लिए एचआरडी के खिलाफ प्रतिशोध, जैसे कि किसानों का विरोध, स्टरलाइट विरोधी आंदोलन, ओडिशा के ज़िंदल विरोधी प्रदर्शन और मेलमा किसान आंदोलन, आम हैं, और इसमें मनमानी गिरफ्तारियां और प्रतिबंधित चिकित्सा पहुंच शामिल हैं। मानवाधिकार रक्षकों को अक्सर न्यायिक उत्पीड़न, मनमाने ढंग से हिरासत में रखने और मनगढ़ंत आरोपों का सामना करना पड़ता है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, जिसे इन उल्लंघनों को संबोधित करने का काम सौंपा गया है, को एचआरडी से संबंधित शिकायतों के अपर्याप्त संचालन के लिए जीएनएचआरआई से महत्वपूर्ण आलोचना मिली है, जो भारत में मानवाधिकारों की वकालत के लिए चल रही प्रणालीगत चुनौतियों को उजागर करता है।

पारदर्शिता और जानकारी तक पहुंच

ग्लोबल टॉर्चर इंडेक्स यातना और दुर्यवहार के जोखिमों को मापने और उनका आकलन करते समय प्रत्येक देश में उपलब्ध सूचना और पारदर्शिता तक पहुंच को रेट करता है। यह सूचना की उपलब्धता के साथ-साथ नागरिक समाज संगठनों द्वारा डेटा एकत्र करने में आने वाली बाधाओं और इसे एक्सेस करने की उनकी क्षमता पर विचार करता है। राज्य की पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए, कानून और व्यवहार दोनों में हर समाज में डेटा पहुंच की गारंटी दी जानी चाहिए। यह संगठनों, पत्रकारों और व्यक्तियों को सार्वजनिक निकायों, प्रोटोकॉल और मानवाधिकारों के उल्लंघन पर आंकड़ों के बारे में जानकारी का अनुरोध करने में सक्षम बनाता है। यह संकेतक किसी देश के भीतर जानकारी तक पहुंचने में चुनौतियों को दर्शाता है, जिसमें प्रत्येक देश और क्षेत्र को दमनकारी, छुपा, परिधि, सुलभ या पारदर्शी के रूप में रेटिंग दी गई है।

भारत का स्कोर इसकी पारदर्शिता और सूचना तक पहुंच के मौजूदा स्तर के हमारे मूल्यांकन के आधार पर छुपाया गया है।



भारत में बदलाव की वकालत: प्रमुख सिफारिशें

सूचकांक में भारत के लिए 5 सिफारिशें शामिल हैं, जो इंडेक्स वेबपेज से ली गई हैं, जो आगामी संस्करणों में यातना विरोधी आंदोलन के भीतर उपलब्धियों की निगरानी के संदर्भ के रूप में काम करेंगी।

1. यातना के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन, इसके वैकल्पिक प्रोटोकॉल और जबरन गुमशुदगी से सभी व्यक्तियों के संरक्षण के लिए कन्वेंशन की पुष्टि करें।
2. प्रभावी साक्षात्कार पर मेन्डेज़ सिद्धांतों को लागू करें और सामूहिक सभाओं के प्रबंधन के लिए आवश्यक प्रशिक्षण के साथ कानून प्रवर्तन और सुरक्षा बलों को प्रदान करें - बल और आग्नेयास्त्रों और अन्य अंतरराष्ट्रीय मानकों के उपयोग पर संयुक्त राष्ट्र के बुनियादी सिद्धांतों का पालन सुनिश्चित करें।
3. मानवाधिकार रक्षकों के खिलाफ आतंकवाद-विरोधी, राष्ट्रीय सुरक्षा और निवारक निरोध कानूनों के दुरुपयोग को रोकें, और गारंटी दें कि वे वैध और शांतिपूर्ण मानवाधिकार गतिविधियों में शामिल होने से अवरोधित नहीं होंगे।
4. इस्तांबुल और मिनेसोटा प्रोटोकॉल के अनुरूप, बीएनएसएस की धारा 196 (2) के अनुसार, न्यायिक मजिस्ट्रेट की देखरेख में, पुलिस या न्यायिक हिरासत में होने वाली सभी हिरासत में होने वाली मौतों की गहन जांच करें। सुनिश्चित करें कि आंतरिक प्रोटोकॉल शव परीक्षण शुरू होने से पहले शरीर को देखने के लिए परिवार के सदस्यों के अधिकारों को बनाए रखते हैं, और गारंटी देते हैं कि परिवार को उसी दिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट और वीडियो रिकॉर्डिंग दोनों प्राप्त हों।
5. प्रत्यायन पर राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थानों के वैश्विक गठबंधन-उप समिति की सिफारिशों को एकीकृत करने के लिये मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम (2019) में संशोधन करें, यह सुनिश्चित करें कि भारत का राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग अपनी स्वतंत्रता, स्वायत्तता और प्रभावी खोजी शक्तियों को बनाए रखे।



आगे के संसाधन

अधिक जानकारी के लिए, पूरा 2025 यातना सूचकांक—विस्तृत डेटा सहित विजुअलाइज़ेशन, अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न, कार्यप्रणाली, और बहुत कुछ—हमारी वेबसाइट पर पहुँचा जा सकता है। यदि आपके कोई प्रश्न हैं, तो महसूस करें हमसे संपर्क करने के लिए tortureindex@omct.org



हमें सोशल मीडिया पर फ़ॉलो करें

हम आपको डेटा का पता लगाने और #GlobalTortureIndex का उपयोग करके सोशल मीडिया पर अपने विचार साझा करने के लिए आमंत्रित करते हैं। सार्थक बातचीत को चलाने के लिए डेटा के साथ जुड़कर और अपने देश की स्थिति को साझा करके जागरूकता फैलाने में हमसे जुड़ें। जागरूकता बढ़ाने और सकारात्मक बदलाव को बढ़ावा देने में आपकी भागीदारी आवश्यक है।

सोशल मीडिया पर हमारे साथ जुड़ें:

